



## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

### विषय

राजकोषीय नीति नियोजन: भारत को एक स्पष्ट  
मध्यम-अवधि योजना की आवश्यकता क्यों है

# राजकोषीय नीति नियोजन: भारत को एक स्पष्ट मध्यम-अवधि योजना की आवश्यकता क्यों है

## संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने वार्षिक राजकोषीय घाटे पर संकीर्ण ध्यान देने के स्थान पर ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर अधिक बल दिया है।

## राजकोषीय नीति के बारे में

- राजकोषीय नीति से अभिप्राय है कि भारत सरकार अपने बजटीय उपकरणों का उपयोग कैसे करती है, जैसे—राजस्व संग्रह (कर, गैर-कर प्राप्तियाँ), व्यय, उधारी और ऋण प्रबंधन।
- इसका उद्देश्य विकास प्राथमिकताओं (बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा) और दीर्घकालिक स्थिरता (घाटा प्रबंधन, ऋण नियंत्रण) के बीच संतुलन स्थापित करना है, साथ ही घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का प्रत्युत्तर देना भी।
- यह मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) के माध्यम से व्यक्त की जाती है।
- राजकोषीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक राजकोषीय घाटा है (सरकारी व्यय और राजस्व के बीच का अंतर), जो सीधे सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करता है।

## वर्तमान राजकोषीय स्थिति एवं भावी लक्ष्य

- राजकोषीय घाटा एवं ऋण:** महामारी वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 9.2% रहा राजकोषीय घाटा 2025-26 में घटकर 4.4% हो गया।
  - 2026-27 के लिए लक्ष्य: राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3%।
  - केंद्रीय सरकार का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 2025-26 में 56.1% से घटकर 2026-27 में 55.6% होने का अनुमान।
- विकास एवं व्यापक आर्थिक परिदृश्य:** आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26) के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में लगभग 7.4% रही, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
  - 2026-27 के लिए वृद्धि दर 6.8–7.2% अनुमानित है, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद लचीलापन दर्शाती है।
- राजस्व एवं व्यय पैटर्न:** कर राजस्व (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) मुख्य स्रोत बने हुए हैं; कर क्षमता सुधारने के प्रयास जारी हैं।
  - गैर-कर राजस्व, विशेषकर आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से प्राप्त लाभांश, अधिक बजट किए गए हैं, जिससे कर बढ़ाए बिना अतिरिक्त राजकोषीय स्थान मिला है।
  - पूँजीगत व्यय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जो 2026-27 में ₹12.2 लाख करोड़ (लगभग ₹12.2 ट्रिलियन) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और विकासोन्मुख पहलों को बढ़ावा देना है।

## मुख्य चिंताएँ एवं मुद्दे

- संकलन के बावजूद उच्च ऋण स्तर:** यदि सरकार 2030-31 तक केंद्रीय ऋण को जीडीपी के  $50 \pm 1\%$  तक घटाने का लक्ष्य प्राप्त भी कर लेती है, तो भी ऋण पूर्व मानकों से बहुत ऊपर रहेगा।
  - FRBM ढाँचे ने 2025 तक केंद्रीय ऋण को जीडीपी के 40% पर रखने की परिकल्पना की थी, जिससे 2031 तक लगभग 10 प्रतिशत अंक का अंतर बना रहेगा।

- **निकट भविष्य में सीमित महत्वाकांक्षा:** अपेक्षा से अधिक आर्थिक वृद्धि को देखते हुए सरकार तीव्र संकलन का प्रयास कर सकती थी।
  - यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि भविष्य में दबाव उत्पन्न होंगे, जैसे—
    - आठवें वेतन आयोग का क्रियान्वयन
    - 2030-31 से पूर्व आम चुनाव से जुड़ी राजकोषीय मांगें
- **सामान्य सरकारी ऋण जोखिम:** राज्य सरकारों का ऋण बढ़ने की संभावना है, जिससे सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी के लगभग 80% पर बना रहेगा, और केंद्रीय स्तर पर हुई प्रगति को संतुलित कर सकता है।

### मुख्य नीतिगत प्रयास एवं पहल

- **केंद्रीय बजट 2026-27 की रणनीति:** राजकोषीय दृष्टिकोण को तीन स्तंभों पर आधारित किया गया—विकास में तीव्रता, जन आकांक्षाएँ, वित्तीय स्थिरता एवं स्थायित्व।
  - **बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय:** सड़कों, रेल, बंदरगाहों, शहरी एवं ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर (हरित एवं सतत बुनियादी ढाँचा) पर केंद्रित रिकॉर्ड वृद्धि।
    - इससे आपूर्ति पक्ष और रोजगार सृजन को सुदृढ़ता मिलती है।
  - **रणनीतिक क्षेत्र समर्थन:** विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक खनिजों को समर्थन, जिससे उत्पादकता बढ़े तथा आयात पर निर्भरता घटे।
  - **एमएसएमई एवं उद्यम समर्थन:** एमएसएमई के लिए तरलता और ऋण प्रावधान में वृद्धि, जिससे रोजगार एवं बुनियादी स्तर पर विकास को बढ़ावा मिले।
- **संरचनात्मक सुधार एवं नीतिगत पहल:**
  - **नियामक सुधार एवं व्यापार सुगमता:** आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने विभिन्न क्षेत्रों में नियमों को सरल बनाने और अनुपालन भार घटाने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित किया है, जिससे दक्षता एवं घरेलू निवेश वातावरण सुधरता है।
  - **श्रम बाज़ार एवं कौशल पर ध्यान:** श्रम सुधार और कौशल विकास पर नीति बल जारी है, जिससे औपचारिक रोजगार एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है।
  - **राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्वास्थ्य:** नीति आयोग की पहल राज्य वित्त को कर क्षमता, ऋण स्थिरता और व्यय गुणवत्ता जैसे संकेतकों पर आँकती है।
    - यह राज्य स्तरीय राजकोषीय अनुशासन को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप करने में सहायक है।

### अन्य प्रयास एवं पहल

- अल्पकालिक घाटे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ऋण-से-जीडीपी लक्ष्य की ओर झुकाव।
- अचानक व्यय कटौती किए बिना क्रमिक राजकोषीय संकलन।
- व्यय गुणवत्ता में सुधार, जिससे दीर्घकालिक विकास को समर्थन मिले।
- बाज़ारों को मध्यम-अवधि राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत।
  - इन प्रयासों ने महामारी-प्रेरित राजकोषीय विस्तार के बाद विश्वसनीयता पुनर्स्थापित करने में सहायता की है।

### आगे की राह

- **प्राथमिक अधिशेष का लक्ष्य:** कम से कम एक छोटा प्राथमिक अधिशेष (ब्याज भुगतान को छोड़कर) चलाना ऋण में कमी को तीव्र करेगा।
- **उच्च नाममात्र जीडीपी वृद्धि बनाए रखना:** ऋण गतिकी इस पर निर्भर करती है कि वृद्धि दर ब्याज दरों से अधिक बनी रहे।
- **केंद्र-राज्य राजकोषीय संकलन का समन्वय:** समग्र रणनीति आवश्यक है, जिससे केंद्र और राज्यों दोनों का ऋण घटे।
- **वित्तपोषण सीमाओं का ध्यान:** घरेलू वित्तीय बचत जीडीपी के लगभग 6% पर है; सरकारी उधारी बढ़ने से निजी निवेश प्रभावित हो सकता है और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।
- **मध्यम-अवधि राजकोषीय नियोजन अपनाना:** सामान्य सरकारी वित्त के लिए पारदर्शी मध्यम-अवधि ढाँचा वार्षिक बजट से परे नीति विश्वसनीयता और बाजार विश्वास को बढ़ाएगा।

### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** मध्यम-अवधि राजकोषीय नियोजन की भूमिका पर चर्चा कीजिए, विशेषकर व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, व्यय की गुणवत्ता सुधारने तथा बाजारों एवं राज्यों की अपेक्षाओं को स्थिर करने में।

[Source: BS](#)

